सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-754
22/12/2015

# मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की

पटना, 22 दिसम्बर 2015 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभाकक्ष में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।

मुख्यमंत्री ने पावर प्वाईंट प्रेजेंटेशन के द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाग की विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुये कई महत्वपूर्ण निदेश दिये। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकार की परियोजनाओं के लिये जो भूअर्जन किया जा रहा है, इसमें अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुये और तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने विशेष रूप से गंगा पथ परियोजना की समीक्षा करते हुये निर्देश दिया कि जहॉ कहीं सरकारी भूमि पर कब्जे की समस्या आ रही है, उसका समाधान राजस्व विभाग, पथ निर्माण विभाग तथा जिला प्रशासन पटना के साथ समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करें।

बैठक के बाद प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार श्री ब्यासजी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि गंगा पथ और गंगा नदी पर निर्माणाधीन ब्रिजेज से संबंधित भूअर्जन शीघ्र करने के लिये उपाय किये जायें। बैठक में प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार ने मुख्यमंत्री को बताया कि दीघा रेल सह रोड परियोजना के लिये बिंद टोली में बसे हुये 205 परिवारों को अन्यत्र बसाने के लिये भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार श्री ब्यासजी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भूमि सुधारों के लिये आवश्यक है कि राज्य में चल रहे विशेष हवाई सर्वेक्षण की गति को तेज किया जाय। प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार ने मुख्यमंत्री को यह बताया गया कि तीन एजेंसियॉ हवाई फोटोग्राफी के लिये लगायी गयी है। हवाई फोटोग्राफी का काम चल रहा है। मार्च 2016 से यह प्रक्रिया और तेज होगी क्योंकि शीत एवं कोहरा के कारण जाड़े में हवाई फोटोग्राफी का काम संभव नहीं हो पाता है। विभाग की कोशिश है कि जून 2016 तक सभी 38 जिलों में हवाई फोटोग्राफी का काम पूरा कर लिया जायेगा। जिन जिलों में हवाई फोटोग्राफी पूरा हो गया है, वैसे जिलों में अगले कैलेण्डर वर्ष में सर्वे के काम के लिये विभाग द्वारा रोडमैप तैयार किया जा रहा है।

प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार श्री ब्यासजी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा संचालित ऑपरेशन भूमि दखल देहानी तथा अभियान बसेरा प्रगति की समीक्षा की तथा कार्यों को और बढ़ाने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को यह भी निर्देश दिया कि सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को अपर जिला भूअर्जन पदाधिकारी की शक्ति प्रदत की जाय ताकि भूअर्जन के काम में तेजी लायी जा सके।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नियमित दाखिल–खारिज सुनिश्चित करने के लिये राजस्व कैम्प प्रत्येक सप्ताह (मंगलवार) को सभी जिलों में आयोजित कराया जाय। प्रत्येक सप्ताह थाना एवं अंचल को संयुक्त रूप से शनिवार को बैठक करने का निर्देश है, जिसमें संवेदनशील भू विवाद के मामलों की समीक्षा होती है। राजस्व विभाग को इस साप्ताहिक बैठकों का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया।

प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार श्री ब्यासजी ने बताया कि बैठक में बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम की धारा– 2डी0(I, II) में आवश्यक संशोधन पर चर्चा हुयी, जिसके तहत एक एकड़ तक जमीन धारित करने वाले परिवारों को भूमिहीन की श्रेणी में माना जायेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य सर्वे का है, जिसे एक समयबद्ध कार्ययोजना के तहत पूर्ण किया जाना चाहिये, विभाग इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अलावे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ0 मदन मोहन झा, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव वित्त श्री रवि मित्तल, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार श्री ब्यासजी, प्रधान सचिव पथ निर्माण श्री सुधीर कुमार, प्रधान सचिव जल संसाधन श्री अरूण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा, सचिव ऊर्जा श्री प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

******